Quest Journals
Journal of Hindi, Political Science and Home Science
Volume 13 ~ Issue 12 (2023) pp: 01-07
ISSN(Online) : 2347 – 2305
www.questjournals.org

Research Paper

भाषाई राज्यों के गठन

सारांश
भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए एक महत्वपूर्ण प्रावधान में राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन के पीछे काम करने वाली अवधारणाओं और कारकों को समझने के लिए यह लेख बहुत मदद करता है। इस लेख का उद्देश्य यह दिखाना है कि भाषाविज्ञान राज्यों पर राज्यों का गठन कैसे हुआ। यह पत्र दार्शनिक पहलू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक वर्तमान मामले पर भी चर्चा करता है।

इस लेख में दी गई सामग्री विभिन्न अन्य विद्वानों के लेखन का विश्लेषण करने के बाद लिखी गई है, इस कारण इसे इसकी प्रामाणिकता मिलती है। यह पत्र भाषाई राज्यों के गठन की शुरुआत का विश्लेषण प्रदान करता है। यह आशा की जाती है कि इस अध्ययन के तहत विश्लेषण पाठकों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को भारत में राज्यों के पुनर्गठन की अवधारणा को समझने में मदद करेगा ताकि वे अपने काम में अधिक कुशल बन सकें।
कीवर्ड: पुनर्गठन, राज्य, संविधान, समितियां, मामले।

***R**eceived 07 Dec., 2023; **R**evised 19 Dec., 2023; **A**ccepted 21 Dec., 2023 © The author(s) 2023.*
P**ublished with open access at **www.questjournals.org

परिचय

रियासतों के विलय और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, और अब भौगोलिक रूप से छोटे और भाषाई रूप से सजातीय क्षेत्रों से नए राज्यों का निर्माण संभव था।

प्रथम भाषाई राज्य का जन्म

1953 में, संविधान की स्थापना के बाद पहली बार किसी राज्य की सीमा को बदल दिया गया था। नतीजतन, एक क्षेत्र जो पहले मद्रास राज्य का हिस्सा था, उसे आंध्र के नए राज्य में विभाजित किया गया था। कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया कि राज्यों की पुनर्व्यवस्था 1951 से अपने चुनाव कार्यक्रम में संबंधित आबादी की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी। जबकि भाषाई विचार महत्वपूर्ण थे, आर्थिक, प्रशासनिक और वित्तीय सहित अन्य विचारों को भी बनाने की आवश्यकता थी।

तेलुगु भाषी आंध्र को मद्रास राज्य से अलग करने की मंजूरी दी गई थी और उपरोक्त समायोजन को कांग्रेस की रणनीति में शामिल करने के बाद एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया था।

अलग आंध्र की मांग बहुत पुरानी है।

लंबे समय से स्वतंत्र आंध्र राज्य की मांग की जा रही है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मद्रास प्रांतीय कांग्रेस समिति के तेलुगु प्रतिनिधियों से परामर्श करने के बाद 1917 में आंध्र के लिए एक अलग कांग्रेस इकाई बनाने का फैसला किया, ताकि उचित समय पर एक तेलुगु भाषी प्रांत की स्थापना की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। 1936 में सिंध और उड़ीसा प्रांत ों की स्थापना के समय आंध्र और कर्नाटक प्रांत भी वांछित थे। मद्रास प्रेसीडेंसी में तेरह से चौदह तेलुगु भाषी जिलों ने अपने प्रांत की स्थापना के पक्ष में अपने सभी प्रभाव को बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसे कांग्रेस के संविधान ने "आंध्र प्रदेश" के रूप में मान्यता दी।

जे.वी.पी. समिति ने एक अलग आंध्र राज्य के निर्माण के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और "प्रत्येक अलग मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद" पुनर्वितरण को ध्यान में रखने की वकालत की।

आंध्र की स्थिति को दूसरों से अलग किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए व्यापक समर्थन प्रतीत होता है और इस भाषाई प्रांत का हिस्सा होने की संभावना वाला सबसे बड़ा कॉम्पैक्ट क्षेत्र एक ही प्रांत के भीतर निहित है। इसलिए, यदि कोई शुरुआत की जानी चाहिए, तो हम सलाह देंगे कि आंध्र प्रांत के विभाजन से उभरने वाले मुद्दे का अध्ययन और जांच की जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इस प्रांत को विभाजित किया जा सकता है या नहीं। यदि आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो हम सलाह देते हैं कि इसे लागू करने के लिए कार्रवाई की जाए।

बबोली के राजा और श्री वीवी गिरि ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान आंध्र के लिए एक अलग प्रांत के निर्माण के लिए एक सम्मोहक तर्क दिया। श्री गिरि ने घोषणा की, "आंध्र एक बहुत ही प्राचीन जाति का है और दुनिया के कई अन्य देशों की तरह ही एक शानदार कीट है," यह याद करते हुए कि कैसे वे पहले एक बड़े राज्य पर हावी थे। हालांकि, श्री गिरि वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संघीय लोकतंत्र की सफलता और भाषाई क्षेत्रों के मुद्दे के बीच संबंध बनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक अलग आंध्र प्रांत का गठन प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के अनुरूप था।

अलग आंध्र राज्य के गठन के लिए कांग्रेस द्वारा आवश्यक शर्तों को बाद में विकसित होने वाले विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। ये शर्तें थीं:

1) राज्य को पारस्परिक रूप से सहमत अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्रों से मिलकर बनना था और मद्रास प्रांत तक ही सीमित होना था।

2) इसका गठन मद्रास प्रांत के अन्य हिस्सों की इच्छा और सहमति से किया जाना था। आंध्र को मद्रास शहर पर अपना दावा छोड़ना था।

राज्य के निर्माण में बाधाएं:

जुलाई 1952 में संसद में बोलते हुए, श्री जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1949 के काम को याद किया, जब तमिल और तेलुगु भाषी लोगों की आपसी सहमति से माड्रेस राज्य को विभाजित करने पर सहमति हुई थी। लेकिन अंतिम क्षण में, मेड्रेस शहर के संबंध में एक संघर्ष दिखाई दिया और राज्य का विभाजन नहीं हो सका।

विभाजन में देरी केवल एक भाषाई प्रश्न नहीं था जो समस्या के लिए शामिल था, जिसका रायलसीमा क्षेत्रों और तटीय जिलों में रहने वाले लोगों के पारस्परिक हित के साथ घनिष्ठ संबंध था। पहली कठिनाई मेड्रेस शहर के बारे में महसूस की गई थी। इसकी आबादी में मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु भाषी लोग शामिल थे। आगामी नए राज्य के लिए राजधानी का चयन करना एक कठिन काम बन गया और यह लोगों के बीच एक क्षेत्रीय संघर्ष में विकसित हुआ। केंद्र सरकार के अनुरोध पर, मद्रास ने एक विभाजन समिति की स्थापना की जिसने भारत सरकार को सिफारिशें कीं। 24 जनवरी, 1950 को केंद्र सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर घोषणा की कि मद्रास शहर की स्थिति, परिसंपत्तियों और देनदारियों के विभाजन, प्रांत की सीमाओं (विशेष रूप से बेल्लारी जिले से संबंधित), रायलसीस की स्थिति और नए प्रांत के वित्त जैसे आवश्यक मुद्दों पर सहमति की कमी ने आंध्र के गठन को अव्यावहारिक बना दिया। समस्या का एक और पहलू यह था कि एक राज्य के लिए पुनर्गठन योजना पड़ोसी क्षेत्रों को भी प्रभावित करती थी, क्योंकि एक भाषाई क्षेत्र दूसरे को छूता था। यह कई स्थानों पर, विशेष रूप से बड़े शहरों में भाषाओं का मिश्रण था। उदाहरण के लिए, हैदराबाद एक ऐसा शहर था और राजनीतिक, आर्थिक और भाषाई दृष्टिकोण से दक्षिण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। बहुत से लोग वहां आए और बस गए; यह कई धार्मिक और भाषाई समुदायों के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता था। इस क्षेत्र में राज्य की सीमाओं में परिकल्पित परिवर्तनों के कई प्रभाव थे। हैदराबाद के विघटन का राजनीतिक महत्व निजाम के पुराने शासन के तत्वों को समाप्त करने और आधुनिक प्रशासन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसे फिर से ढालने में निहित था।

संसद सदस्य डॉ लेंका सुंदरम ने हैदराबाद के विघटन का समर्थन किया और अनुरोध किया कि हैदराबाद के विघटन ने भारत में भाषाई राज्यों के गठन की कुंजी प्रदान की। उन्होंने कहा कि आंध्र देश से संबंधित तीन गंध और अवशिष्ट बिंदु थे -

(1) "मद्रास सिटी: कोई भी आंध्र अपने दावे को आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक आन्ध्र प्रदेश इसे केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र के रूप में स्वीकार करेगा।

(2) हैदराबाद का विघटन: यह अवश्य होना चाहिए और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हैदराबाद प्रदेश कांग्रेस महाराष्ट्रीयन, कन्नड़ और आन्ध्र प्रदेश के एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

(3) रयाल असीमा पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इस आशय के वक्तव्य और प्रतिवक्तव्य आए हैं कि रयाल असीमा आन्ध्र प्रदेश में नहीं आना चाहेंगे।

रयाल असीमा लोग सहयोग करने गए थे।

यह निश्चित है कि अधिक से अधिक सद्भावना और समझ सामने आएगी। लेकिन अगर वे तमिलनाडु से जुड़ने जाते हैं, तो मुझे यकीन है कि उस पर आपत्ति नहीं की जाएगी।

पृथक आंध्र की मांग को लेकर आंदोलन :

1951 की गर्मियों के दौरान, एक अलग आंध्र राज्य के लिए आंदोलन तीव्र हो गया। जुलाई 1952 में प्रधान मंत्री ने भाषाई राज्यों के तत्काल निर्माण के लिए संसद के निचले सदन में कम्युनिस्ट क्रांति के खिलाफ बात की, लेकिन एक अलग आंध्र के लिए अपने समर्थन की घोषणा की, बशर्ते मद्रास शहर और रयाल असीमा पर समझौता हो। 1952 की शरद ऋतु तक आंध्र के नेताओं के बीच मतभेद विकसित हो गए थे कि आंध्र को मद्रास से कैसे अलग किया जाना चाहिए और नए राज्य के संविधान के विवरण पर। मद्रास शहर के स्वभाव पर विवाद विशेष रूप से कड़वा हो गया था। रायलसीमा क्षेत्रों के प्रवक्ताओं ने घोषणा की कि वे कभी भी आंध्र राज्य के गठन के लिए सहमत नहीं होंगे जिसमें मेड्रेस शहर शामिल नहीं था। कम्युनिस्टों ने एक दृढ़ स्थिति बनाए रखी जिसने माड्रेस शहर को शेष मद्रास राज्य को देने की मांग की। आंध्र के कम्युनिस्ट शहर के भविष्य का फैसला करने के लिए जनमत संग्रह का आग्रह करके वास्तव में पार्टी की स्थिति की फिर से पुष्टि कर रहे थे कि 'मद्रास तमिलों का है' प्रधानमंत्री नेहरू ने दिसंबर की शुरुआत में संसद के ऊपरी सदन को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि मद्रास शहर को किसी भी मामले में आंध्र राज्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 1952 के अंत में, एक अलग आंध्र प्रदेश के लिए आंदोलन नाटकीय चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। एक सम्मानित आंध्र देशभक्त और स्वतंत्रता आंदोलन के एक दिग्गज, पोट्टी श्रीरामुलु ने एक अलग तेलुगु भाषी राज्य के गठन के लिए आमरण अनशन किया। पोट्टी श्रीरामुलु की मौत के बाद हिंसक आंदोलन शुरू हो गया था। आंदोलन की भयावह स्थिति को उपाध्यक्ष ने 17 दिसंबर 1952 को सदन में वर्णित किया था, "रेलवे संपत्ति का विनाश, ट्रेनों और टेलीफोन संचार का ठहराव, शांति में व्यापक व्यवधान और नेल्लोर में पुलिस गोलीबारी के कारण जीवन की हानि जो भारत की शांति, स्थिरता और स्थिरता के लिए खतरनाक परिणामों से भरा है। श्री श्रीरामुलु के निधन से उत्पन्न आंध्र प्रदेश में आपातकाल की स्थिति, पुलिस गोलीबारी के परिणामस्वरूप नेल्लोर में तीन लोग मारे गए और बड़ी संख्या में नागरिक घायल हो गए, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर दो करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और इसे रोकने में अधिकारियों की अक्षमता "। जल्द ही यह पता चला कि राज्य को एक साथ रखने का प्रयास करने की तुलना में इसे विभाजित करना बुद्धिमानी होगी और भारत सरकार ने ऐसा करने की घोषणा की। 19 दिसंबर को प्रधान मंत्री नेहरू ने घोषणा की कि उनकी सरकार ने वर्तमान मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों से मिलकर एक आंध्र राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मद्रास शहर को शामिल नहीं किया गया था और न्यायमूर्ति वांचू को निर्णय पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति मिश्रा की रिपोर्ट:

इस फैसले के बाद, न्यायमूर्ति मिश्रा को बेल्लारी तालुक के भविष्य की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति मिश्रा इस फैसले पर पहुंचे कि "बेलेरी तालुक को पूरे मैसूर राज्य में जाना चाहिए, बशर्ते कि संक्रमणकालीन व्यवस्था आंध्र राज्य को सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हो। न्यायमूर्ति मिश्रा की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने पूरे बेल्लारी तालुक को मैसूर राज्य में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। 10 अगस्त 1953 को, "इंधरा राज्य के गठन के लिए प्रावधान करने के लिए" लोक सभा में एक बिल पेश किया गया था। आंध्र राज्य, जो 17 अगस्त 1953 को संसद में उप गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार एक ऐसा प्रांत था जो भाषाई प्रांत के करीब था, 1 अक्टूबर, 1953 को अस्तित्व में आया।

पुनर्गठन का समय:

जैसे ही संसद के निचले सदन में प्रधानमंत्री नेहरू की आंध्र के गठन की घोषणा की गई, एक कम्युनिस्ट सदस्य केरल राज्य की मांग को उठाने के लिए उठ खड़ा हुआ, जबकि उच्च सदन में, एक अन्य कम्युनिस्ट ने कर्नाटक की ओर से इसी तरह का कदम उठाया। एक कम्युनिस्ट संपादकीय में कहा गया है कि आंध्र का गठन "मलयाली, कन्नडिगे, तमिल, गुजराती और महाराष्ट्रीयन लोगों को ऐक्य केरल, मेहे गुजरात और संयुक्त महाराष्ट्र के लिए अपने संघर्ष को अतिरिक्त ताकत देने के लिए प्रेरित करेगा। जे.वी.पी. समिति ने सही कहा था किसी एक की रियायत परिणामी विवादों की मांग को प्रोत्साहित करेगी, यह समुदाय के जीवन और अस्तित्व को प्रभावित करने वाली अधिक जरूरी और दबाव वाली समस्याओं से हमारा ध्यान और ऊर्जा को गंभीरता से हटा देगी। 1. प्रधानमंत्री नेहरू और उनकी सरकार को अभी भी लगता था कि बड़े पैमाने पर राज्य क्षेत्रों में बदलाव की योजना बनाने के लिए उचित अवसर नहीं आया था. यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार राज्य की सीमाओं में व्यापक बदलाव को पूरा करने के लिए अनिच्छुक थी।

प्रांतीय क्षेत्रों के पुनर्वितरण की वांछनीयता को समय-समय पर ब्रिटिश राजनेताओं द्वारा भी मान्यता दी गई थी। वर्ष 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इस तरह के उपक्रम के लिए समय को उपयुक्त माना और इसका परिणाम बंगाल का पहला विभाजन था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 ने एक सामान्य पुनर्वितरण की आवश्यकता को मान्यता दी लेकिन इस तरह के परिवर्तनों के लिए उपयुक्त समय पर विचार नहीं किया। इसने विचार व्यक्त किया कि "पुनर्वितरण "किसी भी मामले में पालन किया जाना चाहिए और न तो संवैधानिक सुधार से पहले और न ही साथ होना चाहिए"। भारतीय वैधानिक आयोग ने प्रांतीय सीमाओं के पुनर्वितरण की भी सिफारिश की, विशेष रूप से शक्तियों के पर्याप्त विकेंद्रीकरण के परिणामस्वरूप प्रांतों की स्थिति में बदलाव के कारण एक संघ की अंतिम स्थापना समाप्त हो गई, जिसमें प्रांत इकाइयां बनाएंगे। आयोग पुनर्वितरण के रास्ते में बहुत बड़ी कठिनाइयों के प्रति सचेत था, लेकिन आग्रह किया कि जिन मुख्य मामलों में प्रांतीय पुनर्समायोजन की आवश्यकता थी, उनकी जांच भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले सीमा आयोग द्वारा की जानी चाहिए।
भारत में सत्ता के हस्तांतरण के बाद अप्रैल 1949 में भाषाई प्रांत आयोग और जेवीपी समिति ने रिपोर्ट दी। ये दोनों निकाय भाषाई प्रांतों के गठन के सीमित प्रश्न से संबंधित थे। हालांकि, उन्होंने प्रांतों के गठन को स्थगित करने का सुझाव दिया।
धार आयोग ने सिफारिश की कि फिलहाल कोई नया प्रांत नहीं बनाया जाना चाहिए और यह सवाल तब उठाया जा सकता है जब इंडी को शारीरिक और भावनात्मक रूप से एकीकृत किया गया हो, भारतीय राज्यों की समस्या हल हो गई हो, राष्ट्रीय भावना मजबूत हो गई हो और अन्य स्थितियां इस आधार पर अनुकूल हों कि -

(एक) भारत रक्षा, भोजन और उत्पादन जैसे प्रांतों के पुनर्वितरण की समस्या की तुलना में अधिक जरूरी समस्याओं के बोझ से दबा हुआ था।

(दो) वह सीमाओं के सीमांकन और बॉम्बे और मद्रास की राजधानियों के आवंटन को लेकर अपनी चिंताओं को और बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकता था.

(तीन) मौजूदा प्रांतों को कई नए प्रांतों में विभाजित करने के आर्थिक परिणामों के लिए बहुत अधिक अध्ययन, तैयारी और योजना के अंत की आवश्यकता थी; (4) उस समय उपलब्ध प्रशासनिक कर्मी नई सरकारों को चलाने के अतिरिक्त बोझ को वहन करने के लिए अपर्याप्त थे। 1. जे.वी.पी. समिति ने पुनर्गठन के लिए उपयुक्त समय नहीं माना क्योंकि इसकी संभावना थी -

(एक) महत्वपूर्ण मामलों से ध्यान हटाना;

(दो) राष्ट्र के लाभ के समेकन की प्रक्रिया को मंद करना;

(तीन) देश के प्रशासनिक, आर्थिक और वित्तीय ढांचे को अस्त-व्यस्त करना और हमारी आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयों के प्रगतिशील समाधान में गंभीरता से हस्तक्षेप करना;

(चार) जब हम प्रारंभिक चरण में थे, तब विघटन और विघटन की ताकतें शिथिल पड़ गईं।

पुनर्गठन की समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि बड़े पैमाने पर योजना बनाने के अपने कार्यक्रम के साथ भारत को स्थायी राजनीतिक इकाइयों के संदर्भ में सोचना पड़ा।

एस.आर. आयोग ने कहा कि "इसलिए, भारत के राजनीतिक मानचित्र को फिर से तैयार करने का कार्य अब इस उम्मीद में किया जाना चाहिए कि जो परिवर्तन लाए गए हैं, वे भारतीय लोगों के पर्याप्त बहुमत को संतुष्टि देंगे।

पुनर्गठन का विरोध करने वालों ने तर्क दिया:

एक) आंतरिक या बाहरी रूप से स्थिति में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ है जो इस दृष्टिकोण को सही ठहराएगा। 1948 में राज्यों के पुनर्गठन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने वाले कारक अब 1952 में गायब हो गए हैं।

दो) विभाजन से पैदा हुई समस्याओं, जिनमें कश्मीर की जटिल समस्या भी शामिल है, का समाधान करना होगा।

तीन) अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और सीमाओं के पार के विकास राष्ट्रीय ऊर्जा और संसाधनों के किसी भी अपव्यय को स्वीकार नहीं करते हैं।

चार) देश का आर्थिक विकास सर्वोच्च प्राथमिकता की मांग कर रहा है और;

पाँच) मौजूदा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर किसी भी तरह के बदलाव से प्रांतीय भावनाएं पैदा होंगी और राष्ट्रीय एकजुटता बिगड़ेगी.

जे.वी.पी. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि पुनर्गठन तब किया जाना चाहिए जब स्थितियां अधिक स्थिर हों और लोगों के दिमाग की स्थिति शांत हो, इन सीमाओं का समायोजन या नए प्रांतों का निर्माण सापेक्ष मामले के साथ और सभी संबंधितों के लाभ के साथ किया जा सकता है। जबकि भाषा एक बाध्यकारी बल है, यह एक अलग भी है। इंडी को सभी विचारों के संतुलन की आवश्यकता थी। इसमें कहा गया है, "हम कुछ वर्षों के लिए नए प्रांतों के गठन को स्थगित करना पसंद करेंगे ताकि हम इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण महत्व के अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और खुद को इस सवाल से विचलित न होने दें।

कुछ लोगों को लगा कि कांग्रेस को जल्द से जल्द पुनर्गठन से निपटना होगा। वे लोगों को यहां तक ले गए हैं और अब उन्हें रिवर्स गियर पर रखना संभव नहीं था। सरदार हुकुम सिंह ने संसद में कहा, "यह पूरी बात हो सकती है और यह कछुआ हो सकता है, अगर इस स्तर पर यह कहा जाए कि क्योंकि कठिनाइयां हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं और हमें वापस जाना चाहिए। यदि अब उन्हें लगता है कि कठिनाइयां हैं, तो निश्चित रूप से हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि उन्हें हल किया जाना है। यह राष्ट्रवादी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि अब यह कहना नौकरशाही है कि जब तक लोग स्वयं पर सहमत नहीं होते, हम उस प्रश्न को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। राष्ट्रीय सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी होगी और उस समस्या को हल करने के लिए आगे बढ़ना होगा जो उसने अपने लिए पैदा की है। जहां तक मैं देख सकता हूं, वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक "महाराष्ट्र एक भाषाई प्रांत के रूप में" शीर्षक के तहत विषय पर चर्चा की है: "भाषाई प्रांतों का निर्माण स्थगित कर दिया जाए"। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित विचार रखे हैं-

एक) भाषाई प्रांतों की मांग में कुछ भी नया नहीं है। छह प्रांत पूर्वी पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, पहले से ही भाषाई प्रांतों के रूप में मौजूद हैं। भाषाई आधार पर पुनर्गठित किए जाने की मांग करने वाले प्रांत (1) बॉम्बे (ii) मद्रास (iii) मध्य प्रांत हैं। जब छह प्रांतों के मामले में भाषाई प्रांतों के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, तो अन्य प्रांत जो उसी सिद्धांत को उन पर लागू करने के लिए कह रहे हैं, उन्हें अनिश्चित काल तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

दो) गैर-भाषाई प्रांतों में स्थिति खतरनाक नहीं तो विस्मयकारी हो गई है और यह किसी भी तरह से उस स्थिति से अलग नहीं है जैसा कि पुराने तुर्की साम्राज्य या पुराने ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य में मौजूद था।

तीन) भाषाई प्रांतों की मांग उसी चरित्र की एक विस्फोटक शक्ति है जो पुराने तुर्की साम्राज्य या ऑस्ट्रो-हंगरियन साम्राज्य को उड़ाने के लिए जिम्मेदार थी। यह बेहतर है कि इसे बहुत गर्म न होने दें जब विस्फोट को रोकना मुश्किल हो सकता है।

चार) जब तक प्रांत अपने संविधान में लोकतांत्रिक नहीं थे और जब तक उनके पास सबसे व्यापक संप्रभु शक्तियां नहीं थीं जो नए संविधान ने उन्हें दी थीं, भाषाई प्रांतों की तात्कालिकता बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन नए संविधान के साथ, समस्या बहुत जरूरी हो गई है।

1955 में, 27 दिसंबर को, डॉ. के. के. पन्निकर ने कहा कि वर्तमान पुनर्गठन के लिए सही समय है। उन्होंने चेतावनी दी कि पुनर्गठन योजना को स्थगित करने से "राष्ट्रीय एकता की जड़ें और कट जाएंगी." एन.वी. गाडगिल ने राज्यों के पुनर्गठन की तुलना स्वतंत्रता की उपलब्धि से की और कहा, "राज्यों के पुनर्गठन की समस्या उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने की समस्या. आखिरकार, राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्रता का एक संगठन है।

सेठ गोविंद दास ने लोक सभा में कहा कि वर्तमान राज्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा आकार दिया गया है। जिस तरह अंग्रेजी भाषा से छुटकारा पाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, उसी तरह राज्यों के इस बंटवारे से छुटकारा पाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। हर दृष्टिकोण से, राज्यों का विभाजन दोषपूर्ण है। एक तरफ उत्तर प्रदेश का विशाल राज्य है तो दूसरी तरफ छोटे आकार के जिलों के कुर्ग, अजमेर और दिल्ली हैं। आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से वर्तमान राज्य संरचना उचित नहीं है। हमें इसे छोड़ना होगा और जल्द से जल्द एक नया पुनर्गठन करना चाहिए।

समाप्ति

सीमा आयोग की मांग का काफी समर्थन किया गया। नायक द्वारा यह कहा गया था कि जब तक इंडी की सरकार केंद्रीकृत थी, तब तक हर युग का प्रशासन और वित्त दोनों केंद्र से प्रदान और निर्देशित किए गए थे, और प्रांतीय सीमा द्वारा ली गई रेखा कम महत्वपूर्ण थी। लेकिन अब प्रांतों ने अपना एक वास्तविक राजनीतिक अस्तित्व हासिल कर लिया है, स्थिति बदल गई है और प्रांतों ने एक संघबद्ध पूरे में एक इकाई का गठन किया है। यह बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रांतीय सीमाओं का समायोजन और एक उचित प्रांतीय श्रृंखला का निर्माण नई प्रक्रिया के बहुत दूर जाने से पहले होना चाहिए। एक बार मोल्ड सेट हो जाने के बाद, किसी भी वितरण को सही करना अभी भी अधिक कठिन होगा। इसलिए यह अत्यावश्यक हो गया है कि भारत सरकार को तत्काल एक तटस्थ आयोग के साथ एक सीमा आयोग का गठन करना चाहिए जो उन मुख्य मामलों की जांच करेगा जिनमें प्रांतीय पुनर्गठन आवश्यक हो गया है और पुनर्गठन के लिए एक योजना तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। लोकसभा में एनसी चटर्जी ने 1952 में कहा था कि संसद को रिपोर्ट देने के लिए एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था, रक्षा और सांस्कृतिक आत्मीयता को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सीमाओं को कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति ने 20 सितंबर को नई दिल्ली में एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें उसने राज्यों के पुनर्गठन के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की और अपील की: -

राज्यों के पुनर्गठन की समस्या पर विचार करने के लिए जल्द से जल्द एक आयोग नियुक्त करने के भारत सरकार के फैसले के मद्देनजर, कार्य समिति का मानना है कि इस महत्वपूर्ण समस्या पर पूर्ण विचार के लिए एक शांत माहौल सुनिश्चित करने के लिए, नए राज्यों के गठन या राज्यों की सीमाओं में कोई भी बदलाव के लिए सार्वजनिक आंदोलन अवांछनीय और अवांछित है।

इसलिए एस.आर. कमिसी आज की आवश्यकता बन गई और इस पर तत्काल ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने मेड्रेस में अपने भाषण में कहा था कि प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमें इसे अच्छी तरह से करने दें। उन्होंने आगे कहा, "हमें इससे डरना नहीं चाहिए या इसके बारे में खेद नहीं होना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक विकास है जो विभिन्न आकारों में पूरे भारत में हो रहा है या होने जा रहा है।

ग्रंथ सूची

एक. राज्य पुनर्गठन आयोग, 1955 का प्रतिवेदन (प्रकाशन प्रबंधक, नई दिल्ली) पैरा 264।

दो. द टाइम ऑफ इंडिया (बॉम्बे) 23 दिसंबर 1953।

तीन. डॉ. मुखर्जी और श्रीमती रामेस्वामी, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, पृष्ठ 17 (द पॉपुलर बुक डिपो, लैमिंगटन रोड, बॉम्बे -7.1955)।

चार. राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की रिपोर्ट। पैरा 25.

पाँच. राजभाषा आयोग की रिपोर्ट, 1956 पृष्ठ 29 (नई दिल्ली, भारत सरकार प्रेस)।

छः. भारतीय और विदेशी समीक्षा, 15 जून, 1970 खंड 7 नंबर 17 पीपी -16-17 (बिजनेस मैनेजर, इंडियन फॉरेन रिव्यू।

सात. भाषाई प्रांत और कर्नाटक समस्या, (कर्नाटक प्रांतीय कांग्रेस, समिति, हुबली 1948 द्वारा बयान) पृष्ठ 68

आठ. राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की रिपोर्ट। पैरा 119.

नौ. भाषाई प्रांत आयोग की रिपोर्ट, 1948, पैरा 181 (भारत सरकार प्रेस)।

दस. राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की रिपोर्ट। पैरा 163.

ग्यारह. भाषाई प्रांत आयोग (1948) को जवाब और ज्ञापन - मद्रास और कर्नाटक के प्रतिनिधियों और संघों द्वारा। (अखिल कर्नाटक एकीकरण संघ. एच.ओ. मंगलोर, 1948) पृष्ठ 112.

बारह. एक नए प्रांत के गठन के लिए एक मामला संयुक्त महाराष्ट्र (पूना, संयुक्त महाराष्ट्र प्रकाशन, 1954) पीपी 14-25।

तेरह. एस.सी. शाह, "राज्य पुनर्गठन आयोग और उड़ीसा!" इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वॉल्यूम 16 पी।

चौदह. लोक सभा में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर 14 दिसम्बर से 23 दिसम्बर, 1955 तक वाद-विवाद

पंद्रह. राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की रिपोर्ट। पैरा 177.

सोलह. राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की रिपोर्ट। पैरा 174.